of State Plans and is reported to have spent Rs. 128.36 lakhs during 1976-77 and 1977-78.

As for Road Transport, the State Govt. are reported to have taken a number of measures including issue of stage carriage permits to Ladakhis for operation within Ladakh; issue of licences for 18 public carriers and 40 jeep taxis to ply as private carriers, maintenance of 12 buses by State Road Transport Corporation for passenger transport in Ladakh and grant of permits for 43 jeep taxis for plying between Srinagar and Leh.

Promotion of Industries in J. & K.

271. SHRIMATI PARVATI DEVI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state what steps have been taken for the promotion and development of industries in Jammu and Kashmir State under the Rural Industrial Project Programme sponsored by the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): Under the Rural Industries Projects Programme sponsored by the Central Government 4 districts of J & K viz., Anantnag, Baramulla, Doda and Kathua have been covered so far. Under this scheme Central assistance is given to the State Government for meeting the full expenditure on the establishment of the project and for organising promotional schemes like Training Programmes and Common Facilities Services Centres. Assistance by way of loan is also provided to the State Government for re-advancing the same at a very low rate of interest to the entrepreneurs for starting industries in the Project Areas.

प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भरता

272. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री 30 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2050 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रक्षेपणास्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितना समय लगेगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से अभी और क्या-क्या कार्यवाही की जानी शेष है ; और

(ख) छापामार युद्धकला में भारत को अब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाने की आशा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) हमारी सशस्त्र सेनाएं जिन राकेटों/प्रक्षेपास्त्रों का उपयोग कर रही हैं उनमें से कुछ पहले हीं देश में बनाए जा रहे हैं। सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रयोग के लिए चुने गये कुछ और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रक्षेपास्त्र बनाने के प्रयत्न जारी हैं। इस कार्यक्रम में सम्बद्ध आधुनिकतम संचार तथा रेडार प्रणालियों का विकास एवं उत्पादन सम्मिलित होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसमें अनुसंधान तथा विकास और चरणबद्ध ढंग से उत्पादन के लिए इन्फ्रास्ट्रकचर बढ़ाना है। इस पर लगभग 7 से 10 वर्ष का समय लगने की आशा है। चूंकि इस क्षेत्र में बहुत ही आधुनिकतम टैक्नालाजी आती है इसलिए समय का मोटा सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। परन्तु सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर प्रक्षेपास्त्रों के प्रयोग तथा साथ ही संघटकों और इस तरह की प्रणालियों के लिए अपेक्षित उप-प्रणालियों के सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में काफी समय लगेगा।

(ख) हमारे कुछ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में अफसरों, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों को गुरिला युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता है। परन्तु